BSNL
Connecting India

Press Media Communication Report

-From Public Relations Cell BSNL CO New Delhi

Publication:	अमर उजाला	Page No:	15
Place:	नई दिल्ली	Date:	18/10/2019

देशहित में जरूरी है बीएसएनएल समस्याएं दूर कर रही सरकार

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दूरसंचार क्षेत्र की मदद का भरोसा जताया

नई दिल्ली। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने घाटे और कर्ज संकट से जूझ रही सरकारी कंपनी बीएसएनएल की मौजूदा समस्याएं दूर करने का भरोसा जताया है। इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीएसएनएल का अस्तित्व में बने रहना देशहित के लिए बेहद जरूरी है। सरकार इस कंपनी को चलाने में आ रही परेशानियों को दूर करने का हरसंभव प्रयास कर रही है।

दूरसंचार मंत्री ने कहा, देश में कहीं भी बाढ़ या चक्रवात जैसी आपदा आती है तो बीएसएनएल सबसे पहले अपनी सेवाओं को मुफ्त कर देती है। लिहाजा देशहित के लिए इसका अस्तित्व में रहना जरूरी है। कंपनी का 75 फीसदी राजस्व सिर्फ कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होता है, जबकि अन्य कंपनियां महज 5-10 फीसदी राजस्व में ही कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर देती हैं। कंपनी के साथ विरासत से जुड़े मुद्दे हैं, जिन्हें सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और इसे चलाने में आ रही दिक्कतों को भी दूर करने का प्रयास जारी है। गौरतलब है कि कंपनी को कई महीनों से लगातार घाटा हो रहा है। एजेंसी

1.75 लाख कर्मी बीएसएनएल में तैनात हैं अभी देश में

घाटे में चल रही कंपनी बंद करना चाहता था वित्त मंत्रालय

पिछले दिनों ऐसी रिपोर्ट आई थी कि वित्त मंत्रालय बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद करना चाहता है। दूसरी ओर, दूरसंचार विभाग ने जुलाई में दोनों कंपनियों को उबारने के लिए पुनरुद्धार योजना पेश की थी जिसे गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई वाले मंत्रिस्तरीय समूह ने मंजूरी भी दे दी है। इस समूह में दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं। हालांकि, बाद में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव पर 80 से ज्यादा आपत्तियां लगाई हैं।

कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन

कर्ज संकट से जूझ रही सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपने कर्मचारियों को अभी तक सितंबर का वेतन नहीं दिया है। बीएसएनएल से करीब 1.75 लाख कर्मचारी जुड़े हैं, जबकि एमटीएनएल में 19 हजार से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। हालांकि, दोनों कंपनियों के प्रबंधन ने पत्र लिखकर 25 अक्तूबर से पहले बकाया वेतन का भुगतान करने का भरोसा दिया है। कंपनी में इस साल की शुरुआत से ही संकट बरकरार है।

दूरसंचार कंपनियों को बेहतर सेवा देने का निर्देश

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को खत्म करने के लिए सरकार कंपनियों की मदद करेगी, लेकिन यह सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर उपभोक्ताओं तक बेहतर सेवा पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को 5जी का हब बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा। 5जी सेवाओं की शुरुआत अभी हो या एक-दो साल बाद, यह सहूलियत के साथ कई तरह की समस्याएं भी लाएगा। लिहाजा उनसे निपटने की तैयारी रखना जरूरी है।